RAJYA SABHA

Thursday, the 7th August, 1997/the 16th Shravana, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the dock.

The Deputy Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास पुनः खोला जाना

*221. **डा0 महेश चन्द्र शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कराची में अपना वाणिज्य दूतावास पुनः खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए है; और

(ग) पाकिस्तान का इस संबंध में क्या रूख रहा है?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) पाकिस्तान सरकार की मांग पर कराची स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को 4.1.1995 को बंद कर दिया गया था । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है । तथापि अभी तक पाकिस्तान ने कोई अनुकूल उत्तर नही दिया है । इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे ।

डा0 महेश चन्द्र शर्मा : महोदया, कल शिकायत थी कि मैं जोर से बोल रहा हूं, आज मैं धीरे बोलूंगा ।

उपसभापति : नही, कल आप गुस्से में बोल रहे थे

डा0 महेश चन्द्र शर्मा : महोदया, भारत के बहुत ही कृत्रिम विभाजन से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और कराची में जहां हमारा पहले वाणिज्य दूतावास था, वह बंद हो जाने के कारण जो लोग उत्तर प्रदेश से और बिहार से वहां गये हुए है, उनको भारत में आने में तकलीफ होती है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर वह क्या कारण थे जिन कारणों से पाकिस्तान ने वह कोंसलेट बंद किया? उसकी जरूर कुछ शिकायतें रही होंगी । तो क्या उन शिकायतों को दूर करने के लिए हमने कोई कोशिश की? इस संबंध में मैं ब्यौरा जानना चाहता हूं ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : महोदया, 4.1.95 को हमारे कराची स्थित कोंसलेट को बंद किया गया । पाकिस्तान की शिकायत थी कि इस राज दूतावास से उनके हित के खिलाफ काम हो रहा था । हम लोगों ने इसको निराधार पाया लेकिन उनके बार-बार कहने के बाद वहां यह स्थिति हो गयी कि वहां राज दूतावास को चलाना मुश्किल हो गया । हमारे लोगों को कहा गया कि आप संख्या को कम करें उन्हें वापिस भेजें । अन्ततोगत्वा यह राज दूतावास बंद हो गया ।

डा0 महेश चन्द्र शर्मा : उपसभापति महोदया, भारतवर्ष के माननीय प्रधान मंत्री जी ने संसद में कुछ एक तरफा घोषणाएं की थी । उन घोषणाओं के आधार पर पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों की सुविधाएं बढ़ायी गयी । मैं जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान इसमें रुचि रखता है कि मुम्बई में उसके राज दूतावास को फिर से प्रारम्भ किया जाए? क्या उन्होंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की है? यदि की है तो हमारा उस संबंध में क्या रिसपोंस हैं ?

SHRl I.K. GUJRAL: Madam, we have indicated to Pakistan that we arc willing To do bilaterally the opening of Karachi and Bombay. At the same time, we have also said that even if consultatcs cannot be opened, we can have visa camps. Pakistan has not rcsponded.

श्री संजय निरूपम : महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कराची में भारत का वाणिज्य दूतावास था, उसी तरह से मुम्बई मे पाकिस्तान का वाणिज्य दूतावास है । वह भी बंद हो गया । पाकिस्तान में मुम्बई का जिन्ना हाऊस अपना वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मांगा था । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या भूमिका है, क्या योजना है जिन्ना हाउस को पाकिस्तान को सौंपने के संबंध में? क्या वह पाकिस्तान को सौंपा जाने वाला हैं? अगर नही सौंपा जाने वाला है तो मैं क्लीयर स्टैंड जानना चाहता हूं ।

श्रीमती कमला सिन्हा : किसी भी देश का राज दूतावास जब कहीं पर भी खोला जाता है तो उस देश को उसे स्वयं लेना पड़ता है । जैसे हम लोगों का कराची में जो राज दूतावास था या आज भी है, वह सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने खरीदी थी । जिन्ना हाऊस भारत की सम्पत्ति है । जिन्ना हाउस को कई साल पहले आई0सी0सी0आर0 को दिया गया । आई0सी0सी0आर0 का वहां कामकाज चलता है । इसलिए जिन्ना हाउस को देने का कोई प्रश्न नही उठता है । मुम्बई में राज दूतावास खोलने के लिए पाकिस्तान को भी कोई प्रॉपर्टी ऐक्वायर करनी पड़ेगी

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : धन्यवाद । उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा । मेरे प्रश्न का (क) भाग यह है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बदलते हुए जो संबंध रहे हैं उसमें समय-समय पर कब कंसोलेटस हिन्दुस्तान में बन्द हुए और कब पाकिस्तान में बन्द हुए और उनकी क्या स्थिति हैं?

मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है कि क्या पाकिस्तान के नकारने पर जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उनका कोई रेसपांस या फेवरेबुल उत्तर नही आया तो उस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसके कोई कारण भी बताये? कंसोलेटस के लिए तो मैं समझ सकता हूं लेकिन वीजा कैम्पस के लिए जैसा उन्होंने कहा कि कोई कारण भी उन्होंने नही बताया या केवल नही कर देने के बाद हम यह उचित नही समझते है कि हम उनसे क्या कारण पूछे?

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदया, शिमला समझौते के बाद 1976 में दोनों ने यह तय किया था कि राजनितिक संबंध सुधारने के लिए एक दूसरे के यहां राजदूतावास खोले जाएं और इस्लामाबाद तथा नई दिल्ली में राजदूतावास खोले गए । उसके बाद 1976 में इस्लामाबाद में दूतावास खोलने के बाद फिर अगस्त 1983 में मुम्बई में पाकिस्तान ने अपना राजदूतावास खोला और हम लोगों ने भी 1978 में कराची में खोला । कराची का हमारा राजदूतावास 4.1.95 में बन्द हो गया । अब हम लोगों ने उसके बाद अनुरोध किया कि हम अपना कराची के राजदूतावास को खोलना चाहते है लेकिन अभी तक हमें उत्तर नही मिला है । आपने जो दूसरा प्रश्न वीज़ा कैम्पस खोलने के बारे में पूछा है कि वीजा कैम्पस खोले जाये तो उसके बारे में भी अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नही मिला है ।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : स्पष्ट उत्तर नही मिला था जिस पत्र के माध्यम से आपने उनसे आवेदन किया वह ही अनुत्तारित रहा है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं । मेरे पहले प्रश्न का जो (क) भाग था वह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में शिमला पैक्ट के बारे में नही है क्योंकि वह तो हमारे संबंधों को सुधारने की ओर एक इशारा था, उम्मीद थी । मैंने तो आपसे यह प्रश्न किया था कि जब से ये दोनों देश अलग-अलग हुए है उसके बाद से समय-समय पर क्या स्थिति रही है, कब वहां पर कंसोलेटस खोले गए, कब बन्द किए गए, कहां खोले गए और क्यों बन्द किए गए और आपने उसके अनुरूप यहां पर क्या कार्रवाई की? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

SHRI I.K. GUJRAL: Madam, the hon. friend has recalled the long history. I need not trace the long history since 1947. It has been full of difficulties. Therefore, the conditions regarding the diplomatic missions have been conditioned by them. We used to have a mission. As a matter of fact, in the beginning of 1947, our embassy was in Karachi till Pakistan shifted its capital from Karachi to Islamabad. Therefore, for some time, we had our mission in Rawalpindi and it went on like this. There were ups and downs all the time. If the hon. Member so wishes, I can send him a detailed note on this to trace the entire history about the closure of our mission. The basic point remains that the last phase of it is that our Consultate in Karachi was closed down on their asking us to do so. That is the main question. They made an allegation at that time that they were not able to get accommodation in Bombay which we never accepted because accommodation is available in Bombay and accommodation can be made available in Bombay. But to link it up with Jinnah's House, that' position is invariable. Jinnah House was never their property. So, the question does not arise.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, the hon. Prime Minister referred to history. Since history has lessons, 1 shall be grateful if detailed information is given to me.

SHRI I.K. GUJRAL: It will be given.

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे लोग जो वहां काम कर रहे है उनके लिए वहां काम करना कठिन हो रहा है,

हमारे दूतावास में काम करने वालों को छुरा घोंपा गया है, उनकी पत्नियों को पीटा गया, वहां पर उनको जेल में इस तरह से रखा जाता है कि वे बाहर नही निकल सकते ।विदेश मंत्रालय मे काम करने वाले ऐसे लोग हैं । जब हमारे प्रधान मंत्री जी विदेश मंत्री थे तब इन्होंने यह कहा कि इस सवाल को ज्यादा न उठायें । उन्हें बड़ा असंतोष था और उनको लगता था कि हमारे प्रोटेक्शन का इंतजाम नही किया जा रहा है । क्या पाकिस्तान के इस पाशविक रवैये के खिलाफ हमने यह सवाल पाकिस्तान से अंतराराष्ट्रीय फोरम में उठाया कि

पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले भारतीयों के साथ अमानुषिक और पाशविक व्यवहार किया जा रहा है?

SHRI I.K. GUJRAL: Madam, you will kindly recall that my hon. friend had raised this issue at that stage as well. We had conveyed to him and I repeat, we took strong exception to those incidents and we had conveyed it to them. We are hoping, and I underline the word *"hoping",* that such incidents would not be repeated.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It would be according to the Geneva Convention.

SHRI I.K. GUJRAL: The Geneva Convention binds everybody, Madam. At the time, there is such a thing as "decent diplomatic behaviour"

SHRI S.B. CHAVAN: Madam, everybody will welcome the steps taken by the hon. Prime Minister, Mr. Gujral, in improving our relations with all our neighbours. But in the context of opening of the Consulates or visa centyes or behaviour of different officials m Pakistan, is it the feeling of the Government that Pakistan is sincerely interested in improving relations with India, especially in view of the fact that the ISI activities arc on the increase? The missile technology which they have obtained from China gives a totally different kind of indication. In this context, what is the thinking of the Government? Having good relations with our neighbours and improving relations with our neighbours is most welcome. But, at the same time, we cannot be obivious to the situation as it is obtaining there today. Even the Amnesty international, which was totally opposed to the idea of declaring that Pakistan is a violator of human rights, has now come out with report saying that they arc the worst violators of human rights and they arc mainly responsible for encouraging terrorist activities in Jammu and Kashmir.

SHRI I.K. GUJRAL: Madam, my hon. friend has a long experience both as Home Minister and as Foreign Minister. He would kindly endorse what I am saying. While we pursue the policy of befriending neighbours, so far as security is concerned, we cannot lower our vigil. We take due notice that is required the acquisition of arms by Pakistan, encouragement to terrorist activities and also activities that are not in the spirit of frcindship. We do take due notice of them.

श्री राम गोपाल यादव : मैडम, प्रश्न पूछने से पहले मै माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एज फौरन मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिन्दुस्तान के अपने पड़ौसी देशों के संबंधों को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । यह बात दूसरी हो सकती है कि किसी देश में शासन करने वाले लोगों का रुख क्या हो । लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें यहां रहने वाले लोगों की और वहां रहने वाले लोगों की मंशा यह रहती है कि इन दोनों देशों के बीच तनाव न हो, संबंध सुधरें । हम देखते हैं कि एक भाई की यहां शादी होती है, बहन पाकिस्तान में होती है यहां नही आ पाती । ऎसे सेन्टीमेन्टल अवसर आते है जहां उस वक्त सारी दीवारें, देश की जो सीमाएं हैं, वे सब टूट जाती है और कोशिश होती है कोशिश करते है, लोग चाहते हैं कि ये तनाव खत्म हो और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरें । भले ही जो चव्हाण साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो गतिविधियां हो रही है वे उसी तरह की गतिविधियां है जो एक शत्रु देश करता है । लेकिन इसके बावजूद अगर हम रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का जो दबाव होता है और सत्ता में बैठे हुए लोगों का रुख कुछ भी हो, उन्हें झुकना पड़ता है । इस संदर्भ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यदि सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी तो उसमें क्या करांची कौसुलेट को री-ओपन करने की बात हुई थी और आगे भी जो वार्ता होगी उसमें इस पर जोर दिया जाएगा, इसके बावजूद कि पाकिस्तान चीन से प्राप्त होने वाले एम-॥ को अप-ग्रेड भी कर रहा है और उन्हें सीमा की तरफ तैनात भी कर रहा है । अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान को भी इसी तरह से करना होगा लेटर और सूनर, लेकिन फिर भी जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इससे अलग हटकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशंस को, नागरिकों की मनोभावननाओं को देखते हुए, उन्हें सुधारने के लिए क्या इस लाइन पर बात प्रभावी ढ़ंग से जारी रखी जाएगी?

SHRI I.K. GUJRAL: Madam, I absolutely share my hon. friend's feelings that the people whose families are divided particularly arc undergoing a great deal of sufferings. It is very inhuman to deny visas to those whose families are divided particularly. It will be recalled. Madam, that India has unilaterally taken several steps. Our difficulties have increased so far as visas are concerned. In 1991 when we had our Consulate in Karachi, in that year alone we issued 1,94,182 visas. Then the Consulate was closed and the number came down. But all the same we have asked our officers to work overtime because the number of officers has also decreased very much. For instance, in 1996 we were able to issue 40,583 visas. In 1997, up to June, we have alrcdy issued 36,064 visas.. We want to sustain this. We have also libraliscd the types of visas, the number of places they can visit and apart from their families a businessman can come, a tourist can come, a student can come and a youth can come. We have also unilaterally relaxed the police reporting. For the seniors, as I said earlier in the House, we have abolished visa fees. We are keen that pcople-to-peoplc relationship should improve on the one side and at the same time for the families which are divided, we should do whatever humanly we can do to see that they do not suffer. I sometimes feel and I say it with a great deal of restraint that the main reason to close down the Karachi Consulate or for asking us to close down the Karachi Consulate was to inflict some sort of strange sadistic pain on those families who live in that region. Tliat is why every time they apply for a visa, they have first to go to Islamabad from Karachi and then go a second time. They arc very poor people. I feel very concerned about their sufferings. It is not a question of religion. It is not a question of citizenship., It is basically a question of human outlook which I share.

So far as defence is concerned, that is a different issue altogether. Naturally we take due notice, as I said just now, of all the activities that take place. We arc determined, I repeat, to safeguard our defence.

SHRI K.R. MALKANI: Madam, not only Parliament but the whole country is with the Prime Minister is wanting to improve relations with Pakistan and developing peoples' level relations in India and Pakistan.

But I am sorry to know that the Government of Pakistan is doing things which make this more and more difficult. Most of the families which have migrated from UP and Bihar are now settled in and around Karachi. They have to go all the way to Islamabad to get a visa. They get back to Karachi to catch a flight or go to Lahore to catch a train. This is very inconvenient. Originally, there used to be actually two routes, Wagha border and Gadra road. I would beg of the Prime Minister to pursue this matter with them. It is very inconvenient particulalry for families most of which happen to be our Muslim brethren. Innumerable Muslim families have split. There are very few families of Hindus which have split. I would request that they should reopen not only the Consulate or at least a Visa Office in Karachi, but also reopen the Gadra Raod, railway route, which was, very much there until 1965.

The trains can come direct from Sindh to Delhi through and from Gadra Road people can go to Lucknow or anywhere else they want Delhi to. If our friends in Pakistan arc really serious about improving relations, they should do something about it.

SHRI I.K. GUJRAL: Madam, I think my hon. friend, for whom I have great respect faulted on one formulation. The fault is not that of the Government of India. The Government of India shares the same feeling as my hon. friend Mr. Malkani has expressed. We are keen even to open the railway. Wc have opened the Chennai airport for them. We arc also now permitting anybody poming from one airport to go out from another airport; that is, coming from say Delhi and going out from Bombay. We arc

permitting that. Wc have again signed the agreement for a railway route through wagha. All this is continuing. We are trying our best and I assure you, Madam, and through you hon. Member that India will never lag behind in trying to come to the rescue of those people and those families who arc suffering. So far as visas arc concerned, we have extended one more facility. For those living in Karachi and who have to go long distancnes to Islamabad, they can apply through fax so that they don't have to undertake a second journey. That also has been done. Wc have also approached the Pakistan Governmeni to let us increase the number of officials posted in Islamabad. At the same time I must say to the credit of our own officials even their wives are working overtime to help in issuing of visas. All that is humanly possible is being done by us. If we cannot go to Karachi, I cannot help it if they don't permit it. But our concern and our feelings go with all those who are now inflicted with pain.

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी : मैं प्रधानमंत्री जी की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सुधारने की, उनकी सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं । हम सब को यह बात समझनी चाहिये कि पाकिस्तान बना है नफरत की बुनियाद पर लेकिन हमने जो पाकिस्तान कबूल किया है वह नफरत की बुनियाद पर नही बल्कि उदारता की बुनियाद पर । ठीक है हमारे साथ नही रहना चाहते तो अलग बना लो । इसलिए हमारे रवैये में और पाकिस्तान के रवैये में बुनियादी फर्क रहेगा । मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम पाकिस्तान के जो आवाम है, वहां के जो शहरी है, उनके ख्यालात में और समझदारी में बदलाव आ रहा है और यह बदलाव इस बात का संकेत है, इशारा है कि जो हालत आज है, वो हालात हमेशा रहने वाले नही है । हकूमतें चाहें या नही चाहें लेकिन आवाम उठ खड़े होंगे और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में हकूमतों को मजबूर कर देंगे ।मैं इस सिलसिले में यह चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो अपनी कोशिश जारी रखे हुए है, उसका जारी रखें और पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके जो सफीर है या उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन से जब भी हमारे लोगों की मुलाकात हो तो इस बात की ज़रूर चर्चा करनी चाहिये जिस तरह से हमने सहलियतें दी हैं आने के लिए, आप भी विज़ा देने में सहूलियत करें । यहां पाकिस्तान का जो दूतावास है आम तौर से शिकायतें मिलती है कि लोगों को बहुत परेशान किया जाता है वीज़ा देने में और लोग बहुत परेशान होते है । इसकी तरफ भी कोशिश होनी चाहिये । अगर हमारे रवैये में बदलाव आया है, हम बेहतर ताल्लुकत चाहते हैं, हम आसानी चाहते है तो आप भी इन्सानी जज्बे को सामने रखते हुए लोगों की मुश्कलात को सामने रखते हुए अपनी रवैये में तबदीली करें वीज़ा देने में फ्राखदिली का सबूत दें ।

†**مولانا حبیب الرحمان نعمانی:** میں پردھان منتری جی کی جو کوشش ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات سدھارنے کی انکی سراھنا کرتا ہوں۔ تعریف کرتا ہوں۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہئے کہ پاکستان بنا ہے نفرت کی بنیاد پر لیکن ہم نے جو پاکستان قبول کیا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ادارتا کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہئے ہو تو الگ بنالو اسلئے ہمارے رویہ میں اور پاکستا ن کے رویہ میں بنیادی فرق رہے گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم پاکستان کے جو عوام ہیں وہاں کے جو شہری ہیں انکے خیالات میں اور سمجھداری میں بدلاؤ آرہا ہے اور یہ بدلاؤ اس بات کا سنکیت ہے۔ اشارہ ہے کہ جو حالات آج ہیں وہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ حکومتیں چاہیں یا نہیں چاہیں۔ لیکن عوام اٹھ کھڑے ہوگے اور تعلقات کو بہتر بنانے میں حکومتوں

†[ ]Transliteration in Arabic Script

کو مجبور کر دینگے۔ میں اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی جو اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اسکو جاری رکھیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں انکی ذمہ داری ہے انکے جو سفیر ہیں یا انکے فارن منسٹر ہیں ان سے جب بھی ہمارے لوگوں کی ملاقات ہوتو اس بات کی ضرور چرچہ کرنی چاہئے جسطرح سے ہم نے سہولتیں دی ہیں آنے کے لئے ۔ آپ بھی ویزہ دینے میں سہولیت کریں۔ یہاں پاکستان کا جو دوتا واس ہے۔ عام طور سے شکایتیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے ویزہ دینے میں اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اسکی طرف بھی کوشش ہونی چاہئے۔ اگر ہمارے رویہ میں بدلاؤ آیا ہے ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم آسانی چاہتے ہیں تو آپ بھی انسانی جزبہ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رویہ میں تبدیلی کریں اور ویزہ دینے میں فراخدلی کا ثبوت دیں۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a suggestion actually. I don't think there is any question. Whatever the Member suggested was his view. So, while negotiating, you may take this into account.

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जो मेरे आनरेबल दोस्त ने कहा कि मैं उसके साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन करें क्या? कई दफा मुश्किल ऐसी होती है कि सिर फोड़ने की खातिर सिर को ढूंढ़ते हैं, सिर मिल नही रहे हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: now there are five more people who want to put questions. We have already taken 25 minutes for this.

Absolute Number of poor in the country

*222. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:†
DR. MOHAN BABU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the absolute number of poor in the country in 1951 and 1994 and the percentage of population thereof; and

(b) the steps proposed for poverty alleviation to accelerate the development of the country's human resources?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Planning Commissioner estimates incidence of poverty at national and state level on "the basis of quinquennial consumer expenditure surveys conducted by the National Sample Survey Organisation (NSSO). The first quinquennial survery relates to the period 1972-73, Subsequently, these surveys were conducted in the years 1977-78. 1983, 1987-88 1993-94. the